अनुसार इसकी कहां तक पुष्टि समर्थन करते हैं ;

(ग) क्या श्री बी० के० नेहरू द्वारा इस प्रकार के वक्तव्यों के बाद भी सरकार उन्हें वहां पर अपने प्रतिनिधि के रूप में बनाये रखना देश के हित में समझती है; और

(घ) श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्री आर० के० नेहरू और श्री बी० के० नेहरू के अलावा नेहरू परिवार के अन्य किन सदस्यों को अथवा नजदीकी रिश्तेदारों को विदेशों में राजदूत नियुक्त किया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां 16 जून, 1976 के 'सन्डे टाइम्स' में प्रकाशित एक पत्र में यू० के० में भारत के हाई कमिश्नर श्री बी० के० नेहरू ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा था : "अतः मैं बन्दी बनाए गए लोगों की संख्या से संबंधित आरोपों या उन्हें तंग किये जाने के बारे में कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं समझता अपितु मात्र एक दिलचस्प विषय के रूप में इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कुछ अंश यहां उद्धरित करना चाहूंगा जिसमें नजरबंदों पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाये गए थे : 'राज्य अधिकारियों द्वारा नजरबंदों के बारे में दिखाई गई चिन्ता, जिनको रहने को अच्छा स्थान दिया गया, अच्छा खाना दिया गया और जिनके अच्छा व्यवहार किया गया, लगभग घर के व्यक्तियों प्रति दर्शाई गई चिन्ता के समान थी" । किन्तु संदर्भाधीन यह उद्धरण न्यायाधीश श्री एम० एच० बेग द्वारा दिये गये एक अन्य फैसले से है ।

(ख) पिछली सरकार ने आपातकाल की घोषणा, अन्य कार्यवाहियों तथा उसके द्वारा उठाये गए कदमों का औचित्य समझाने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों को तत्संबंधी पृष्ठभूमि-सामग्री के साथ निर्देश दिये थे । विदेश स्थित भारतीय मिशनों में सेवा-रत प्रतिनिधियों का यह भी एक वक्तव्य है कि वे सतारूढ़ सरकार के कार्यों और नीतियों को यथासंभव विश्वसनीय ढंग से समझाएं । हाई कमिश्नर द्वारा उद्धरित अंश में व्यक्त विचारों से मैं सहमत नहीं हूं ।

(ग) जैसा कि 23 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1630 के उत्तर में कहा जा चुका है ऐसी उम्मीद की जाती है कि श्री बी० के० नेहरू लगभग तीन महीने में अपना कार्यकाल पूरा कर के अपने पद का कार्यभार छोड़ देंगे ।

(घ) श्री ए० के० दर जो राजदूत थे और अब सेवानिवृत्त हो गए हैं । श्री ए० एन० मेहता आजकल मैक्सिको में भारत के राजदूत के पद पर कार्य कर रहे हैं । ये दोनों अधिकारी भारतीय विदेश सेवा के हैं जो उक्त सेवा के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते राजदूत नियुक्त किये गए थे ।

Correction of Answer to Unstarred Question No. 2800 dt. 7-7-1977 re: Orders for not charging from out-door patients.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): In Unstarred Question No. 2800 put in the Lok Sabha on 7-7-1977, it was asked by Shri R. K. Mhalgi

whether Central Government have urged the State Governments not to charge any patients visiting hospitals for out-door treatment; if so, when the appeal was made; and the response thereon—Statewise. We have given a negative reply with reference to all parts of the Question.

However, the reply to part (a) of the Question is actually in the affirmative. With reference to part (b), it may be stated that an appeal was made on the 4th of June, 1977.

As regards part (c) of the Question it may be stated that so far only eight replies have been received from the State Governments/Union Territories as under:—

(i) Government of Orissa—"No levy is being charged from patients visiting Government hospitals clinics for out-door treatment, nor is there any proposal at present for such levy".

(ii) Government of Karnataka—"In our State, patients are treated free in Government-run hospitals, except in the city of Bangalore where the referral system has been introduced and where, in consequence, they are charged 25 paise per patient. However, the Superintendents of the hospitals have been given the discretionary power to exempt the registration fee, if the patients are really poor and unable to pay".

(iii) Government of Gujarat—"In the State of Gujarat we have not been charging any such fees in all the dispensaries and hospitals run by the State Government."

(iv) Government of Punjab—"In Punjab Government Hospitals/dispensaries/Primary Health Centres, a parchi fee @ 0.10 paisa is charged from the outdoor patients other than Government Servants and persons entitled to free medical treatment. For poor people with no income of their own the Medical Officer, in charge of a hospital/dispensary/Primary Health Centre, had the discretion not to charge any parchi fee. This discretion is, however, limited to 10 per cent of the attendance for the day".

(v) Government of Sikkim—"In the State of Sikkim no levy is being charged from patients visiting the out-door department of the various State Hospitals. All the treatment to the poor patients is provided free of charge from the State funds".

(vi) Administration of Andaman and Nicobar Islands—"At present no fee is being levied from out-door patients in so far as the hospitals/dispensaries in this Union Territory are concerned".

(vii) Government of Himachal Pradesh—"In this State no fee is levied on the poor for their treatment. For exempting the other people from such a levy, the matter is under consideration of this Government".

(viii) Government of Rajasthan—"Luckily in the Government hospitals of Rajasthan no such levy is charged from the patients".